High Project were completed on 2nd June 1977 in Washington. It is expected that the loan agreement will be signed shortly.

Interest on Bank Loans to Educational Institutions

771. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) whether in April, 1977 Government of India have received written representation from Maharashtra requesting them to charge interest on Bank loans to educational institutions at the rate of 4 per cent and not at the rate of Rs. 12½ per cent; and

(b) if so, what action Government have taken or propose to take on the said representations and when?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) Government do not appear to have received any such representation.

(b) Does not arise.

पर्यटन विकास सम्बन्धी केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत झालावाड़ जिले में किये जा रहे कार्य

772. **श्री चतुर्भुज** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन विकास सम्बन्धी केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत झालावाड़ जिले में क्या कार्य किये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : साधनों की तंगी तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण झालावाड़ में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत कोई पर्यटन सम्बन्धी योजना प्रारम्भ नहीं की गई है ।

राजस्थान नहर और चम्बल कमांड क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से ऋण

773. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर और चम्बल कमांड क्षेत्र परियोजना के लिये विश्व बैंक की ओर से आर्थिक सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और जिन परियोजनाओं पर यह रकम खर्च की जाएगी उनका ब्यौरा क्या है और यह योजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) राजस्थान नहर और चम्बल सिंचाई क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ने 1590 लाख डालर की वित्तीय सहायता देने का वचन दिया है । इसमें से 830 लाख डालर राजस्थान नहर के लिए, 520 लाख डालर राजस्थान में आने वाले चंबल सिंचाई क्षेत्र विकास के लिए और 240 लाख डालर मध्य प्रदेश के चंबल सिंचई क्षेत्र विकास के लिए रखे गये हैं । आशा है कि ये परियोजनाएं क्रमश: 30 जून, 1980 और 31 दिसम्बर, 1978 तक पूरी हो जाएंगी ।

Multinational Corporation

774. SHRI D. B. CHANDRA GOWDA: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) the number of multinational corporations functioning at present in the country; and

(b) the amount remitted abroad by these units during the last three years

in form of profit and dividends, and the amount of foreign exchange earned by India during this period, year-wise as a result of the operations of these Corporations?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) As on 31-3-1976 (latest period for which information is available) there were 171 Subsidiaries and 481 Branches of foreign companies operating in India. There is no precise definition of multinational corporation. Hence for the purpose of the question, information is given about foreign companies.

(b) According to the Reserve Bank, the total remittances towards profits and dividends effected by foreign companies during the last three years were as below:

	(Rs. crores)
1973-74	45·57
1974-75	20·63
1975-76	34·42

Information about the foreign exchange earned by these companies during this period is not readily available.

भारत, यूगोस्लाविया और मिश्र के बीच आर्थिक सहयोग के विषय पर बातचीत

775. **श्री उग्रसेन :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, यूगोस्लाविया और मिश्र के बीच आर्थिक सहयोग पर त्रिपक्षीय वार्ता का जो सूत्रपात लगभग 10 वर्ष पहले किया गया था वह अब सर्वथा निश्चेष्ट हो गई है और वार्ता को पुन: आरम्भ करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या इस दिशा में अब तक प्राप्त उपलब्धियों का मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) वार्ता पुन: कब तक आरंभ की जायेगी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). भारत, मिश्र और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार विस्तार तथा आर्थिक सहयोग करार पर 23 दिसम्बर, 1967 को हस्ताक्षर हुए थे और यह 1 अप्रैल, 1968 से लागू हुआ था। इस करार का मुख्य उद्देश्य तीनों देशों के बीच निर्दिष्ट माल के आदान-प्रदान के सम्बन्ध मे टैरिफ अधिमान प्रदान करना है। इस प्रयोजन के लिये, तीनों देशों ने 134 टैरिफ शीर्षों की साझी सूची बनाई है और जब वे परस्पर इन उत्पादों का व्यापार करते हैं तो परम मित्र राष्ट्र दर का 50 प्रतिशत टेरिफ अधिमान देते हैं। औद्योगिक संयुक्त उद्यमों, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, नौवहन, पर्यटन, वित्त, बैंकिंग तथा बीमा जैसे अन्य विभिन्न क्षेत्र में त्रिपक्षीय कार्यकलापों को भी इस करार में रखा गया है ।

विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए मंत्रियों तथा इस करार के अन्तर्गत गठित कार्यकारी दल की समय समय पर बैठकें होती हैं। तीनों देशों के मंत्रियों की चौथी बैठक काहिरा में 2 तथा 3 मई, 1976 को हुई थी। मंत्रियों ने टैरिफ अधिमान के प्रभाव का अध्ययन करने के बाद तीनों देशों की बीच व्यापार संवर्धन के लिये अनेक उपायों का सुझाव दिया था, जैसे साझी सूची का विस्तार, विद्यमान साझी सूची की मदों पर टैरिफ कटौती बढ़ाना, साझी सूची में मदें जोड़ना और गैर-टैरिफ प्रतिबन्ध हटाना ।

व्यापार तथा टैरिफ सम्बन्धी त्रिपक्षीय कार्यकारी दल की दिसम्बर, 1976 में जब बैलग्रेड में बैठक हुई तो उसने इन सिफारिशों का अनुसरण किया। 1976 में काहिरा में हुई